to file with the Registrar of Newspapers an audited statement. Whether or not any newspaper has filed it or not, for that, you will have to give me some time. Put a specific question and I shall answer.

MR. SPEAKER: He cannot give you an off-hand answer.

SHRI NIREN GHOSH: Have any irregularities been found in the audited accounts?

MR. SPEAKER: You put a separate question for that.

SHRI H. N. BAHUGUNA: Will the hon. Minister be pleased to state whether any newspaper has been prosecuted for non-fulfilment of the statutory provisions referred to by him? Let him answer.

SHRI N. K. P. SALVE: For this, I will need notice.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Sir, look at the question.

MR. SPEAKER: I have seen.

SHRI H. N. BAHUGUNA: I want to make a submission. The Minister should do his home work better. At least you must say that. (*Interruption*)

MR. SPEAKER: Look here. Why are you trying to get up unnecessarily? I know my job and I shall do it.

I would like to clarify here that the question pertains to a certain reference in a particular situation. If it is outside, you have to give a separate notice I shall allow you to put the question. There is no problem. When it is not concerned with a particular newspaper, how can I allow this?

SHRI SUNIL MAITRA: Kindly see the question again—(a) whether it is a fact (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: I have seen. Why are you trying to get up? Next question. Mr. Goyal.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Are you satisfied with the answer?

MR. SPEAKER: You will have to give a separate question. I will allow it.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: It is a part of the question.

MR. SPEAKER: Put a specific question and get a specific answer. Next question. Mr. Goyal, you put your question (*Interruptions*) I will not let anybody to evade. Mr. Goyal.

Demand and supply of newsprint

124. SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that newspapers in the country are facing a critical newsprint situation;

(b) what is the present position of newsprint within the country and the extent of full gap between demand and supply;

(c) the quantity of newsprint imported in the current year; and

(d) the necessary steps to be taken by Government in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN): (a) No, Sir.

(b) to (d). The Newsprint Advisory Committee had estimated that the total consumption of newsprint for the current financial year (1982-83) would be around 3.60 lakh tonnes. Out of this, 1.50 lakh tonnes was estimated as indigenous production. The balance quantity of 2.10 lakh tonnes was to be met by drawing down 26,000 tonnes from the State Trading Corporation buffer stocks of imported newsprint and 1.84 lakh tonnes by imports through the S.T.C.

2. Upto the end of September 1982, the total release of both imported and indigenous newsprint has been about 1.46 lakh tonnes consisting of 1.03 lakh tonnes imported through the S.T.C. and 43,000 tonnes from indigenous production.

As against the estimated production of 1.50 lakh tonnes of indigenous newsprint, some shortfall is apprehended due to various problems facing the newsprint mills, including power shortages, labour unrest, etc. This shortage will have to be met from other sources including the possibility of using cream wove paper by newspapers and periodicals. The production and distribution of indigenous newsprint is being continuously reviewed and monitored to ensure adequate supplies. The S.T.C. has also been asked to import 1.20 lakh tonnes between October and December, 1982 so as to ensure adequate availability of newsprint to newspaper and build up a buffer stock of about 30,000 tonnes.

MR. SPEAKER: You could have put this on the Table.

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं, माननीय मंत्री जी ने जो न्यूज़-प्रिन्ट की गई पालिसी की घोषणा की है, जिसकी मांग बहुत समय से चलती आ रही थी, उसका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ जिस प्रकार का आपने उत्तर दिया है, न्यूज़ प्रिन्ट एडवाइज़री कमेटी की डिमाण्ड को देख कर जो 3.60 लाख टन आती है, उस कैलकुलेशन के अनुसार इंडीजिनस प्रोडक्शन, एस०टी०सी० के बफर स्टाक की रिलीज़ और इम्पोर्ट—इन सभी के माध्यम से आपने यह बताने की कोशिश की है कि हम रिक्वायर्मेन्ट को मीट करने की पोज़ीशन में हैं लेकिन क्या यह सही नहीं है कि हमेशा ही देश में न्यूज़ प्रिण्ट की शार्टेज को लेकर, उसकी क्वालिटी को ले कर और प्राइस को ले कर एक असंतोष रहा है ? आज हमारे देश में जो इण्डस्ट्रीज़ पेपर प्रोड्यूस कर रही हैं उसमें भी ड्राप की गुंजायश है, सरकार ने भी इस बात को माना है। इन हालात को देखते हुए क्या मंत्रालय यह निर्णय लेने की स्थिति में है कि जो बड़े अखबार हैं उनको तो डाइरेक्ट इम्पोर्ट करने की इजाजत दे दी जाए और एस०टी०सी० के द्वारा जो आप कैनेलाईज़ेशन करते है उसमें जो मध्यम और छोटे अखबार हैं उन्हीं को आप एस०टी०सी० के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहें—इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है, यह मैं जानना चाहता हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : जहां तक न्यूज़-प्रिन्ट को प्रोवाइड करने का सवाल है, सप्लाई करने का सवाल है, अखबारों को हम लगातार देते आ रहे हैं और उसमें कोई क्रिटिकल प्राब्लम नहीं है।

अब रहा यह सवाल कि क्या बड़े अखबारों को डाइरेक्ट इम्पोर्ट करने की इजाजत दी जाए तो इस सम्बन्ध में मेरा आपसे यह निवेदन है कि एस०टी०सी० के थ्रू जो हम कैनेलाईज़ेशन करते हैं उसके दो कारण हैं—कि तो यह है कि आज दुनिया में कागज़ बहुत ज्यादा एवेलेबल है इसलि बड़े अखबारों को वह मिल सकता है और वे डम्प कर सकते हैं लेकिन अगर हमारी दूरदर्शिता की नीति न रहे, तो आने वाले दिनों में जब न्यूज़प्रिन्ट की शार्टेज होगी तब उनको न्यूज़-प्रिन्ट नहीं मिल पायेगा। इसलिए एक लांग-टर्म पालिसी को देखते हुए गवर्नमेण्ट कैनेलाईज़ेशन का ऐसा इन्तजाम किया गया है कि हमारे अखबारों को कभी भी न्यूज़-प्रिण्ट की शार्टेज न हो। दूसरी बात यह है कि बड़े अखबारों को हम डायरेक्ट इम्पोर्ट करने दें और छोटे अखबारों को न

करने दें —इसका तो कोई रीजन हमारी समझ में नहीं आता। अगर करना है तो हर कोई करे और नहीं करना है तो कोई भी नहीं करेगा। न्यूज़-प्रिन्ट के इम्पोर्ट में विदेशी मुद्रा का भी एक ज़बर्दस्त फैक्टर रहता है। अभी जो पालिसी निर्धारित की गई है वह विदेशी मुद्रा को देखते हुए, पेपर की जरूरत को देखते हुए और सरकार के दायित्व को देखते हुए एक बहुत बीक पालिसी अभी तक रही है, ऐसा हम मानते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, न्यूज़ प्रिन्ट का इम्पोर्ट और बफर-स्टाक एस० टी० सी० डिएट करती हैं। न्यूज़ प्रिन्ट की प्राइस के बारे में हमेशा शिकायत है कि एस० टी० सी० मनमाने ढंग से फिक्स करती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्राइस फिक्स करने के लिए एस० टी० सी० का क्या फार्मूला है, कौन-कौन से फेक्टर्स की कितनी-कितनी प्राइस आती है? क्या यह सही है कि विशेषकर जो ओवरसीस सप्लायर हैं, जैसे बंगलादेश कनाडा, यू० एस०, साउथ कोरिया और चैकोस्लोवाकिया आदि, इनका रेट पांच हजार रुपये टन ही नहीं बल्कि 4,700 रु० टन से लेकर 4,800 रु० टन आता है, जबकि एस० टी० सी० 6,000 रु० टन चार्ज करती है? क्या यह सही है कि एस० टी० सी० ने जो बफर स्टॉक पुराना इम्पोर्ट किया हुआ है, उसको प्राइस 7,600 रु० से 7,905 रु० कर दिया है? ऐसी स्थिति के अन्दर मंत्री महोदय क्या हाउस को एशोयर करेंगे कि एस० टी० सी० जिन जिन आधार पर जो प्राइस तय करती है, उसको पब्लिकली एनाउन्स करेंगे और भविष्य के अन्दर प्राइस तय करने के लिए न्यूज़ प्रिन्ट प्रोड्यूसर्स के रिप्रेजेन्टेटिव का एस० टी० सी० के अन्दर शामिल करेंगे?

श्री एन० के० पी० सालवे : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 140 इसी प्रश्न से सम्बन्धित है। . . . .

The question and the answer given read like this.

"(a) whether it is a fact that the newspaper industry had expressed its dissatisfaction about the basis on which the State Trading Corporation had fixed the price of imported newsprint; and

(b) whether it is proposed to associate the newspaper industry with the purchase negotiations?"

The answer given to this question is like this:

"(a) Yes, Sir.

(b) The State Trading Corporation imports newsprint in consultation with its Newsprint Purchase Committee and the Newsprint Advisory Committee of this Ministry. On both these committees members of the newspaper industry are already represented.

We have also now decided to include two representatives of the newspaper industry in the newsprint price fixation committee, constituted by this Ministry."

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। एस० टी० सी० जो प्राइस तय करती है और रिलीज़ कर रही है और खास तौर से उसने बफर स्टाक की प्राइस बढ़ा दी है—क्या आप इसको उचित मानते हैं और पब्लिक इन्टरेस्ट के अन्दर यह प्राइस फैक्टर क्या है, इसको आप एनाउन्स करना चाहेंगे?

श्री एन० के० पी० सालवे : आप सही फर्मा रहे हैं। एस० टी० सी० को

इजाजत नहीं है कि वह मनमाने ढंग से कीमत ले ले। जो कमेटीज वहां पर हैं, उनमें न्यूज पेपर इण्डस्ट्री के प्रतिनिधि भी हैं—ये सब मिल कर तय करते हैं कि किस कीमत पर आयेगा। जैसा कि आप न्यूज प्रिन्ट की बाहर की कीमतों का जिक्र कर रहे हैं और यहां पर सस्ती हैं, इसमें दिक्कत यह है कि वैस्टर्न कन्ट्रीज में एक ग्लट है कि किसी भी कीमत पर इसको डम्प करने के लिए तैयार हैं। हमारी लांगटर्म पालिसी को सामने रखते हुए, जिस कीमत पर हमने आयात किया है, जिस का हमारा लांग-टर्म कान्ट्रैक्ट है, उसी आधार पर हम चलेंगे। एक दफा तो कमेटी को बैठाकर कीमत तय हो जाती है, उसी कीमत पर हम अखबारों को न्यूज प्रिन्ट देते रहते हैं।

श्री अशफाक हुसैन : अध्यक्ष महोदय, अभी अखबारों से समाचार मिला है कि न्यूज प्रिन्ट के डिस्ट्रीब्युशन का नया तरीका सरकार इवाल्व कर रही है। वह तरीका यह है कि बजाय एस० टी० सी० के जरिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अब राज्य सरकारों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन किए जाने की बात सुनने में आई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो नया तरीका अपनाया जा रहा है, क्या यह अखबार वालों की राय और मश्विरे से किया जा रहा है या जो नई पालिसी सरकार की बनी है, बिहार प्रेस बिल के तहत, या प्रदेश सरकार को एक शिकंजे में पकड़ कर दिया जा रहा है ?

श्री एन० के० पी० सालवे : अध्यक्ष महोदय, न्यूज प्रिंट की जितनी नीतियां निर्धारित की जाती हैं, वे तीन कमेटीज जिनका मैंने जिक्र किया है, शामिल की जाती हैं।

Loss due to poor quality of coal supplied to fertilizer plants

*127. DR. A. U. AZMI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the coal supplied to the two fertilizer plants at Talcher and Ramagundam contains 45 per cent ash though plants were designed to take coal with 17 per cent ash thereby leading to use of more coal to produce less ammonia resulting in shooting up of the cost;

(b) whether it is also a fact that the poor quality coal has led to highly corrosive micro-components in the gas and some sections of the plants have been fully corroded in no more than four months;

(c) if so, the reasons thereof; and

(d) steps taken to check the recurrence/loss?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VASANT SATHE): (a) to (d). A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) The coal based fertilizer plants at Talcher and Ramagundam were designed to take coal with 21 to 22 per cent of ash and ash plus moisture not more than 26 per cent. The coal supplied to Talcher fertilizer plant contained ash content of 30 to 35 per cent on an average and sometimes more than 35 per cent ash. This led to higher consumption of coal per tonne of ammonia leading to increase in cost of production. The coal supplied to Ramagundam plant is more or less as per required specifications.

(b) Due to presence of various corrosive gases in the raw synthesis gas, some of the equipments were corroded. Remedial measures have already been implemented to remove the corrosive gases and affected equipments have been replaced.